"जनता की आवाज, सच का आईना"

श्री डूंगरगढ़ टाइम्स

9414917401 ♦ सोमवार ♦ 02 नवम्बर, 2026 ♦ Email : sridungargartimes@gmail.com ♦ अंक - 903



दानदाता परिवारों ने सभा पदाधिकारियों को सौंपी भवन की चाबियां, वाचनालय, पुस्तकालय, बैठक कक्ष और कार्यालयों की मिली सुविधा



श्रीडूंगरगढ़ टाइम्स

2 नवंबर 2026। श्री जैन श्वेतांबर तेरापंथी सभा, श्रीडूंगरगढ़ के नवनिर्मित तीन मंजिला सभा एवं पुस्तकालय भवन का रविवार को विधिवत हस्तांतरण किया गया। दिवंगत सेठ बिंजराज पुगलिया परिवार एवं दिवंगत धर्मचंद्र पुगलिया परिवार के सौजन्य से पुनर्निर्मित इस भवन की चाबियां दानदाता परिवारों की ओर से सभा के वरिष्ठ उपाध्यक्ष तुलसीराम चौरड़िया एवं मंत्री प्रदीप पुगलिया को सौंपी गईं। सुबह 9:30 बजे आयोजित कार्यक्रम में दोनों दानदाता परिवारों के सदस्य एवं सभा के पदाधिकारी और कार्यकारिणी सदस्य मौजूद रहे।

दानदाता परिवारों ने जताई प्रसन्नता

श्रीडूंगरगढ़ टाइम्स। हस्तांतरण समारोह में दिवंगत बिंजराज पुगलिया परिवार की ओर से सुमेरमल पुगलिया, राजेंद्र कुमार पुगलिया, विमल कुमार पुगलिया, अरुण कुमार पुगलिया, पवन नाहटा, रतन श्यामसुखा, नीरू पुगलिया एवं सभा सह मंत्री अक्षत पुगलिया उपस्थित रहे। वहीं दिवंगत धर्मचंद्र पुगलिया परिवार की ओर से सभा अध्यक्षा सुशीला पुगलिया मौजूद रहीं। इस अवसर पर भीकमचंद पुगलिया (जयपुर) ने भवन निर्माण की परिकल्पना एवं कार्ययोजना की जानकारी देते हुए दोनों दानदाता परिवारों सहित विमल कुमार पुगलिया, कांतिकुमार पुगलिया, संजय बरड़िया एवं प्रदीप पुगलिया के सहयोग के प्रति आभार जताया।

विमल कुमार पुगलिया ने निर्माण कार्य में सुमेरमल पुगलिया के मार्गदर्शन तथा कांती कुमार पुगलिया सहित अन्य सहयोगियों के योगदान की जानकारी दी। सभा मंत्री प्रदीप पुगलिया ने निर्माण कार्य में विमल कुमार पुगलिया, कांती कुमार पुगलिया एवं संजय बरड़िया के सहयोग की सराहना की। उन्होंने बताया कि निर्माण के दौरान विमल कुमार पुगलिया ने निर्माण सामग्री के भंडारण एवं जलापूर्ति की व्यवस्था स्वेच्छा से उपलब्ध करवाई। वहीं स्थानीय पड़ोसी प्रदीप मालू के सहयोग के प्रति भी आभार व्यक्त किया।

पुस्तकालय और वाचनालय सहित मिलेगी विभिन्न सुविधाएं

श्रीडूंगरगढ़ टाइम्स। नवनिर्मित भवन को आधुनिक सुविधाओं एवं संस्था की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। भवन के भूतल पर व्यावसायिक उपयोग के लिए स्थान निर्धारित किया गया है। प्रथम तल पर वाचनालय, कार्यकारिणी बैठक कक्ष, कोषाध्यक्ष एवं लेखा कार्यालय तथा अध्यक्ष और मंत्री के कार्यालय बनाए गए हैं। द्वितीय तल पर विशाल पुस्तकालय विकसित किया गया है, जो समाज के विद्यार्थियों एवं नगरवासियों के लिए ज्ञानार्जन का केंद्र बनेगा। वरिष्ठ नागरिकों सहित सभी आयु वर्ग के लोगों की सुविधा के लिए भवन में लिफ्ट की व्यवस्था भी की गई है। हस्तांतरण के बाद दानदाता परिवारों के सदस्यों ने सभा अध्यक्षा सुशीला पुगलिया एवं मंत्री प्रदीप पुगलिया को भवन का अवलोकन करवाया। इसके बाद दोनों पदाधिकारियों को उनके नवनिर्मित कार्यालय कक्षों में आसन ग्रहण करवाया गया। कार्यक्रम में सह मंत्री संजय बरड़िया, कोषाध्यक्ष तोलाराम पुगलिया, संगठन मंत्री पांचीलाल सिंघी, विनोद भादानी, विकास डागा, महेंद्र दुगड़, प्रदीप मालू, लूणकरण बोथरा, मंजू बोथरा, रेखा देवी भादानी, मधु झाबक, लक्ष्मीपत भादानी, धनराज पुगलिया, कमल बोथरा, अशोक बैद, नरेंद्र डागा एवं विजयराज सेठिया सहित कार्यकारिणी सदस्य उपस्थित रहे।

वाहन मालिक को जेल भेजने की धमकी दी, धोखाधड़ी के आरोप में दो के खिलाफ मामला दर्ज

श्रीडूंगरगढ़ टाइम्स 2 नवंबर 2026। वाहन मालिक को जेल भेजने की धमकी देने और धोखाधड़ी करने के आरोप में दो व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। गुसाईसर बड़ा निवासी मुखराम पुत्र कैलाशचंद जाट ने गांव बाना निवासी राधेश्याम बाना, भरपालसर निवासी ओमप्रकाश मेघवाल पर धोखाधड़ी के आरोप लगाए है। परिवादी ने पुलिस को बताया कि उसके रजिस्टर्ड शुदा वाहन टाटा प्रेमा उसके नाम रजिस्टर्ड है। इस वाहन को परिवादी ने 17 जून 2026 को राधेश्याम बाना के पक्ष में बेचान कर दिया। इकरारनामे के अनुसार फाईनेंस की बकाया किश्त 29,24,000 रूपए वाहन खरीद करने के बाद श्रीराम फाईनेंस कंपनी को राधेश्याम बाना द्वारा 34 किश्तों में चुकता करनी थी। आरोपी ने मात्र 3 किश्तें चुकाई। परिवादी ने गाड़ी के कागजात भी आरोपी के सुपुर्द कर दिए थे।उसके बाद आरोपी ने किश्तों का भुगतान नहीं किया। 19 सितंबर को परिवादी को विहार ट्रांसपोर्ट से फोन आया और परिवादी को कहा कि आपकी गाड़ी में गेहूं का माल लोड किया था और माल चालक ने बचे दिया है। परिवादी ने कंपनी को बताया कि उसने वाहन बेच दिया है। उसने दोनों आरोपियों से संपर्क कर वाहन की किश्त भरने और दो तीन दिनों में वाहन को अपने नाम करवाने की बात कही। 21 सितंबर को आरोपी ने उसे धमकाते हुए वाहन को अपने नाम नहीं करवाने और इस गाड़ी से अवैध काम में चलाकर भेजने व जेल भिजवाने की धमकी दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच एएसआई राजकुमार को सौंप दी है।

कार्मिकों को आवंटित हुए मतदान केंद्र, रिटर्निंग अधिकारियों को ग्राम पंचायतें, आज रवाना होगे मतदान दल



श्रीडूंगरगढ़ टाइम्स 2 नवम्बर 2026। पंचायती राज आम चुनाव-2026 के तृतीय चरण में जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्यों के मतदान के लिए मतदान दलों को मतदान केंद्र और ग्राम पंचायतों के पंच-सरपंच के मतदान के लिए रिटर्निंग अधिकारियों को ग्राम पंचायत आवंटन के लिए तृतीय रेंडमाइजेशन एनआईसी परिसर में रविवार को हुआ। इस दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी निशान्त जैन और आब्जर्वर नवनीत कुमार के मार्गदर्शन में हुए रेंडमाइजेशन के दौरान उप जिला निर्वाचन अधिकारी उम्मेद सिंह रतनू और जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, संकल्प शर्मा मौजूद रहे। तृतीय चरण में लूणकरणसर, श्रीडूंगरगढ़ और रीडी पंचायत समिति क्षेत्र में आने वाले जिला परिषद, पंचायत समिति सदस्यों सहित पंच और सरपंच पदों के लिए निर्वाचन होंगे। इसके लिए मतदान दलों की रवानगी आज सोमवार (2 नवम्बर) को प्रातः 7:30 बजे प्रशिक्षण के पश्चात राजकीय पॉलीटेक्निक कॉलेज परिसर से होगी। प्रत्येक कार्मिक को समय पर उपस्थित होने के निर्देश दिए गए हैं। अन्यथा संबंधित के खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी। तृतीय चरण में 112 ग्राम पंचायतों के मतदान के लिए कुल 402 मतदान केंद्र मतदान निर्धारित किए गए हैं। मतदान दलों में पीठासीन अधिकारी एवं प्रथम, द्वितीय, तृतीय तथा चतुर्थ मतदान अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। तृतीय चरण के तहत श्रीडूंगरगढ़ की 33 ग्राम पंचायतों में 123, रीडी की 31 ग्राम पंचायतों में 104, लूणकरणसर की 48 ग्राम पंचायतों में 175 केंद्रों पर मतदान होंगे। तृतीय चरण में पंचायत समिति सदस्यों के लिए मतदान 3 नवम्बर को प्रातः 7 से सायं 6 बजे तक होगा। पंच-सरपंच पद के लिए नामांकन की नामांकन प्रक्रिया 4 नवंबर को तथा निर्वाचन 5 नवंबर को प्रातः 7 से सायं 6 बजे तक होगा। मतदान के तुरंत बाद मतगणना संबंधित ग्राम पंचायत मुख्यालय पर की जाएगी। वहीं 6 नवंबर को उप सरपंच का चुनाव होगा। वहीं बैठक में पंचायती राज आम चुनाव के चतुर्थ चरण की पंचायत समितियों में मतदान दलों के गठन के लिए द्वितीय रेंडमाइजेशन भी रविवार को किया गया। चतुर्थ चरण के तहत नोखा, पांचू एवं जसरासर की कुल 92 ग्राम पंचायतों के 426 केंद्रों में चुनाव होंगे।

मोदी, शाह, ज्ञानेश वोट चोरी के जिम्मेदार, सबको मिलेगी सजा - राहुल



कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष तथा लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर वोट चोरी के जरिए लोकतंत्र को कमजोर करने का आरोप लगाते हुए कहा है कि वोट चोरी करने वाले बच नहीं सकते और उनके खिलाफ कार्रवाई होगी और उनके किए की उन्हें ज़रूर सजा मिलेगी। श्री गांधी ने विपक्षी इंडिया गठबंधन की वोट बचाओ, देश बचाओ रैली को यहां रविवार को रामलीला मैदान में संबोधित करते हुए कहा कि श्री कुमार को मुख्य चुनाव आयुक्त के पद से हटाना विपक्ष का पहला लक्ष्य है और वह पद से हटेंगे तथा जेल जाएंगे। उन्होंने कहा, आप संविधान से बड़े नहीं हैं। लंबे समय से वोट चोरी होने का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश, हरियाणा, छत्तीसगढ़ तथा महाराष्ट्र समेत कई राज्यों के चुनावों में धांधली की गई है। कांग्रेस नेता ने दावा किया कि 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद करीब साढ़े तीन करोड़ मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए। करीब 60 मतदाताओं में से एक मतदाता का नाम सूची से हटा और इस तरह करीब 15 प्रतिशत वोटरों को सूची से हटाया गया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) और विपक्ष के बीच मतों का अंतर केवल तीन प्रतिशत था। मतदाता सूची से नाम हटाने की प्रक्रिया ने चुनाव परिणामों को प्रभावित किया और यह देश के नागरिकों की आवाज छीनने जैसा है। श्री गांधी ने कहा कि यह सामान्य चोरी नहीं बल्कि देश के हर नागरिक की आवाज और अभिव्यक्ति के अधिकार की भी चोरी है। उनका कहना था कि मुख्य चुनाव आयुक्त यदि वोटो की हेरा फेरी नहीं करते, वोट चोरी नहीं करते तो श्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री और श्री अमित शाह गृह मंत्री नहीं बन सकते थे। उन्होंने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई), प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), न्यायपालिका और नौकरशाही जैसी संस्थाओं पर कब्जा किए जाने का आरोप लगाते हुए कहा कि इन संस्थाओं का उद्देश्य देश के लोगों के हितों की रक्षा करना है लेकिन मोदी सरकार का इन संस्थाओं पर कब्जा है और इन पर नियंत्रण के कारण युवाओं, गरीबों, किसानों और श्रमिकों को उनका हक नहीं मिल रहा है, जबकि अडानी और अंबानी जैसे बड़े उद्योगपतियों के हितों को प्राथमिकता दी जा रही है। उन्होंने कहा कि हमारे लोगों को ऐसा भारत नहीं चाहिए, जहां गरीबों के पैसे का इस्तेमाल कुछ चुनिंदा लोगों के फायदे के लिए हो और आम नागरिकों को सम्मान न मिले। उनका कहना था कि एक गरीब आदमी अगर बैंकों से लोन लेता है और लौटने की स्थिति में नगीन है तो उसे दंडित किया जाता है लेकिन उद्योगपति पैसा डकार रहे और उनका कुछ नहीं हो रहा है। कांग्रेस नेता ने कहा कि किसान मेहनत करता है और अपने खून-पसीने से देश को सींचता है, तो उसे उसका फल मिलना चाहिए। इसी तरह विद्यार्थियों को उनकी मेहनत और पढ़ाई का उचित परिणाम मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि वोट चोरी के लिए जिम्मेदार लोगों को जवाब देना होगा और देश की जनता को न्याय मिलना चाहिए। श्री गांधी ने कहा कि कांग्रेस और विपक्षी गठबंधन के लोग किसी से नफरत नहीं करते हैं और ना ही किसी को अपना दुश्मन मानते हैं। उन्होंने कहा कि विपक्ष के लोग नफरत नहीं मोहब्बत की दुकान चलाने वाले लोग हैं, हिंसा के बजाय अहिंसा में विश्वास करने वाले लोग हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री मोदी, श्री शाह और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने देश में नफरत फैलाई है, जिससे देश को नुकसान हो रहा है। उन्होंने कहा कि देश के संविधान और उसकी आत्मा पर हमला हुआ है और इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देश के लोग नफरत और दुश्मनी नहीं भाईचारा, प्यार और मोहब्बत चाहते हैं।

दो युवाओं की याद में मानव सेवा का संकल्प, बिग्गा में आज लगेगा रक्तदान शिविर



श्रीडूंगरगढ़ टाइम्स

2 नवम्बर 2026। क्षेत्र के गांव बिग्गा में दिवंगत रेवंतराम शर्मा एवं वीरेंद्र सारस्वत (विक्की) की प्रथम पुण्यतिथि के अवसर पर आज सोमवार को रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा। शिविर को लेकर गांव में तैयारियां पूरी कर ली गई है। रविवार को आपणो गांव श्रीडूंगरगढ़ सेवा समिति के सेवादारों द्वारा शिविर के पोस्टर का विमोचन किया गया। इस दौरान समिति के अनेक सदस्य मौजूद रहे। शिविर का आयोजन सोमवार, 2 नवंबर को गांव के बड़ा बास स्थित तावणियां पंचायत में सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक होगा। इसमें गांव के युवाओं, ग्रामीणों सहित आसपास के क्षेत्र के सामाजिक कार्यकर्ताओं के शामिल होने की संभावना है। समिति सदस्यों ने क्षेत्र के युवाओं से अधि काधिक संख्या में शिविर में पहुंचकर रक्तदान करने की अपील की है। आयोजकों ने बताया कि रक्तदान किसी जरूरतमंद को नया जीवन देने का पुनीत कार्य है। दिवंगत युवाओं की स्मृति को मानव सेवा से जोड़ते हुए यह शिविर आयोजित किया जा रहा है। आयोजकों ने आमजन से इस सेवा कार्य में भागीदारी निभाने का आह्वान किया है।

वाणिज्यिक रसोई गैस सिलेंडर फिर महंगा, दिल्ली में 10 रुपये बढ़ी कीमत



त्योहारों से पहले वाणिज्यिक रसोई गैस (एलपीजी) सिलेंडर के दाम एक बार फिर बढ़ गए हैं, हालांकि घरेलू इस्तेमाल वाले सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। सार्वजनिक तेल विपणन कंपनियों ने रविवार से दिल्ली में 19 किलोग्राम वाले वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर की कीमत बढ़ाकर 2,820 रुपये कर दी है। अक्टूबर में इसकी कीमत 2,810 रुपये थी। इस प्रकार दिल्ली में यह 10 रुपये महंगा हुआ है। अन्य शहरों में भी कीमतों में कर और परिवहन लागत के आधार पर थोड़े-बहुत अंतर के साथ लगभग इतनी ही बढ़ोतरी की गई है। इस साल अगस्त के बाद यह लगातार तीसरी बार है जब वाणिज्यिक रसोई गैस महंगी हुई है। तीन बार में दिल्ली में इसकी कीमत 82 रुपये प्रति सिलेंडर बढ़ी है। गत 28 फरवरी को पश्चिम एशिया संकट की शुरुआत के बाद से ही वाणिज्यिक रसोई गैस सिलेंडर के दाम ऊपर बने हुए हैं। पश्चिम एशिया संकट से पहले के स्तर से दिल्ली में अभी इसकी कीमत 1,079.50 रुपये ऊपर है। वहीं, घरेलू इस्तेमाल वाले 14.2 किलोग्राम के सिलेंडर के मूल्य में गत 07 जून के बाद से कोई बदलाव नहीं किया गया है। घरेलू एलपीजी सिलेंडर की दिल्ली में 942 रुपये और कोलकाता में 968 रुपये है। मुंबई में यह 941.50 रुपये का और चेन्नई में 957.50 रुपये का है।

मोदी सरकार की विदाई नजदीक, ज्ञानेश कुमार को इस्तीफा देना होगा - खरगे

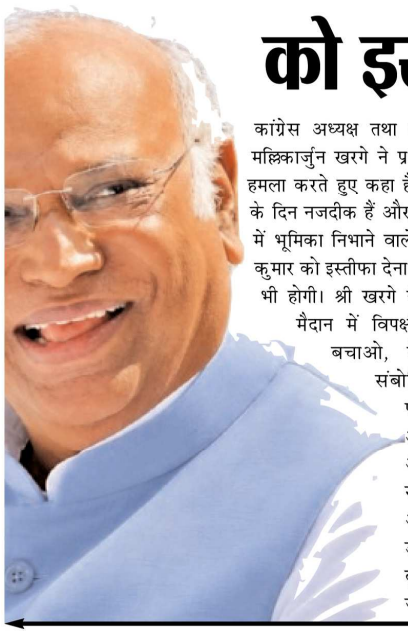

कांग्रेस अध्यक्ष तथा राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला करते हुए कहा है कि मोदी सरकार की विदाई के दिन नजदीक हैं और देश में वोट चोरी की साजिश में भूमिका निभाने वाले मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को इस्तीफा देना होगा तथा उनके खिलाफ जांच भी होगी। श्री खरगे ने रविवार को यहां रामलीला मैदान में विपक्षी इंडिया गठबंधन की वोट बचाओ, देश बचाओ महारैली को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और मुख्य चुनाव आयुक्त जनता की आवाज समझ लें, क्योंकि वे लोगों का अधिकार नहीं छीन सकते। उन्होंने कहा कि यह आजादी की दूसरी लड़ाई है और विपक्ष इसे जीतकर रहेगा। कांग्रेस अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के नाम पर करीब 14 करोड़ मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं। उन्होंने सवाल किया कि हटाए गए नामों में कितने विदेशी नागरिक थे। उन्होंने दावा किया कि छह राज्यों में 10 करोड़ मतदाताओं में केवल 1,600 विदेशी मिले हैं, जिनमें अधिकतर नेपाल के नागरिक हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा घुसपैठियों के नाम पर झूठ बोल रही है और मतदाता सूची में बदलाव का इस्तेमाल चुनावी फायदे के लिए किया जा रहा है। श्री खरगे ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार को महंगाई, बेरोजगारी, किसानों और मजदूरों की समस्याओं की चिंता नहीं है बल्कि उसे अपनी कुर्सी की चिंता है। उन्होंने कहा कि चुनिंदा पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाया जा रहा है, जबकि सार्वजनिक उपक्रमों के निजीकरण से रोजगार और आरक्षण पर खतरा पैदा हो रहा है। उन्होंने किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की कानूनी गारंटी देने का वादा पूरा नहीं होने का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में मतदाता सरकार चुनते हैं लेकिन मोदी सरकार अपनी पसंद के मतदाता चुनने में लगी है। उन्होंने सवाल किया कि क्या युवाओं, किसानों और कमजोर तबकों के वोट इसलिए काटे जाएंगे कि वे सरकार से सवाल पूछते हैं और अपने अधिकारों की मांग करते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि लोकतंत्र में कोई सरकार स्थायी नहीं होती और जनता ही तय करती है कि कौन सत्ता में रहेगा। उन्होंने प्रधानमंत्री को चेतावनी देते हुए कहा कि वे अहंकार में यह कहना बंद करें कि भाजपा 30 या 40 साल तक सत्ता में रहेगी। उन्होंने कहा कि मतदान का अधिकार संविधान से मिला है, कोई खैरात नहीं, और इसे कोई छीन नहीं सकता।



54 अदालतें, एयरपोर्ट जैसी सुरक्षा... राजस्थान में बनेगा हाईटेक कोर्ट कॉम्प्लेक्स, ओम बिरला ने किया शिलान्यास



राजस्थान को जल्द ही आधुनिक सुविधाओं से लैस एक हाईटेक जिला न्यायालय परिसर मिलने जा रहा है। कोटा में 290 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बनने वाला यह एकीकृत कोर्ट कॉम्प्लेक्स प्रदेश के सबसे बड़े और आधुनिक न्यायालय परिसरों में शामिल होगा। यहां 54 अदालतें एक ही परिसर में संचालित होंगी। न्यायिक कामकाज के लिए डिजिटल डिस्प्ले, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और आधुनिक सम्मेलन कक्ष जैसी सुविधाएं विकसित की जाएंगी। वहीं, सुरक्षा व्यवस्था एयरपोर्ट की तर्ज पर होगी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजय के. अग्रवाल और विधि मंत्री जोगाराम पटेल ने रविवार को इस परियोजना का शिलान्यास किया। नया परिसर केवल भव्य भवन तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि न्यायिक अधिकारियों, अधिवक्ताओं, कर्मचारियों और वादकारियों की जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार किया जाएगा। पार्किंग, लाइब्रेरी, स्वास्थ्य केंद्र और अन्य जरूरी सुविधाएं एक ही जगह उपलब्ध होंगी। परियोजना को जुलाई 2028 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए 3.21 हेक्टेयर भूमि आवंटित की गई है। मुख्य भवन का क्षेत्रफल करीब 4.47 लाख वर्गफीट होगा।

सात फ्लोर, 11 लिफ्ट और 1468 वाहनों की पार्किंग

न्यायालय परिसर में बेसमेंट, भूतल और पांच मंजिलें होंगी। भवन में कुल 11 लिफ्ट लगाई जाएंगी और पूरा परिसर वातानुकूलित रहेगा। पार्किंग की क्षमता 1468 वाहनों की होगी। इसमें 734 कारों और 734 बाइक-स्कूटर के लिए जगह निर्धारित की गई है। स्टेशन रोड से कोर्ट परिसर तक पहुंच आसान बनाने के लिए 80 फुट चौड़ी चार लेन की कनेक्टिंग सड़क भी बनाई जाएगी। सुरक्षा के लिहाज से प्रत्येक प्रवेश द्वार पर मेटल डिटेक्टर लगाए जाएंगे। तीन स्थानों पर सामान की जांच के लिए मशीनें स्थापित होंगी। भवन में आग से बचाव और अग्निशमन की आधुनिक प्रणाली रहेगी। बिजली की अनुमानित जरूरत 4.5 मेगावाट होगी। इसके लिए 250 किलोवॉट क्षमता का सोलर प्लांट भी लगाया जाएगा।

बिरला बोले-भवन से ज्यादा जरूरी आम आदमी को न्याय

शिलान्यास समारोह में ओम बिरला ने कहा कि नया न्यायालय परिसर बनना बड़ी उपलब्धि है, लेकिन न्याय व्यवस्था की असली सफलता आम आदमी को सरल, सुलभ, त्वरित और निष्पक्ष न्याय मिलने में है। अदालत में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को सम्मान के साथ बैठने और अपनी बात रखने की सुविधा मिलनी चाहिए। इसके लिए न्यायपालिका, अधिवक्ताओं और प्रशासन को मिलकर काम करना होगा। उन्होंने कहा कि अलग-अलग स्थानों पर न्यायालय संचालित होने से लोगों को परेशानी होती है। अब सभी न्यायालय एक ही परिसर में होंगे। अधिवक्ता कक्षों के निर्माण की निविदा प्रक्रिया भी जल्द शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं। बिरला ने बताया कि कोर्ट के साथ मिनी सचिवालय बनाने की योजना पर भी काम चल रहा है, ताकि लोगों को प्रशासनिक कार्यों के लिए अलग-अलग जगहों पर नहीं जाना पड़े।

पुराने मुकदमों के निस्तारण पर भी जोर

हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजय के. अग्रवाल ने कहा कि न्यायालय की पहचान उसकी इमारत से नहीं, बल्कि निष्पक्ष न्याय से होती है। नए परिसर में महिलाओं, दिव्यांगजनों, वरिष्ठ नागरिकों और कमजोर वर्गों की सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा जाए। उन्होंने कहा कि डिजिटल तकनीक न्यायिक व्यवस्था के लिए जरूरी है, लेकिन यह न्याय का विकल्प नहीं हो सकती। न्यायिक अधिकारियों और अधिवक्ताओं को पुराने लंबित मुकदमों के जल्द निस्तारण पर भी ध्यान देना चाहिए। कोटा के संरक्षक न्यायाधीश सुदेश बंसल ने अधिवक्ताओं के लिए चैंबर और बैठने की बेहतर व्यवस्था की जरूरत बताई। उन्होंने आग्रह किया कि ऐसी सुविधा प्रदेश के सभी जिलों में विकसित की जाए। विधि मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि नए परिसर में वादकारियों और अधिवक्ताओं को आधुनिक सुविधाएं एक ही स्थान पर मिलेंगी। समारोह में जिला एवं सत्र न्यायाधीश हेमराज गौड़, अभिभाषक परिषद अध्यक्ष भारत सिंह अडसेला, महासचिव शम्भू सोनी सहित कई न्यायिक अधिकारी और अधिवक्ता मौजूद रहे।

राजस्थान की विकास योजनाओं पर केंद्र से चर्चा करेंगे मुख्य सचिव

जयपुर। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश की विकास योजनाओं को गति देने और केंद्र सरकार के साथ समन्वय मजबूत करने के लिए मुख्य सचिव श्री वी. श्रीनिवास 2 एवं 3 नवंबर को नई दिल्ली के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे 17 से अधिक बैठकों में भाग लेकर राजस्थान की प्रमुख योजनाओं, विकास परियोजनाओं एवं प्रशासनिक सुधारों से जुड़े विषय रखेंगे। श्री श्रीनिवास 2 नवंबर को गृह कार्य संबंधी संसदीय स्थायी समिति से मुलाकात करेंगे। दो दिवसीय दौरे में विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उनकी बैठकें प्रस्तावित हैं। इन बैठकों में डिरेगुलेशन एवं कंप्लायंस रिडक्शन पर भी चर्चा होगी। इसके तहत नियमों और प्रक्रियाओं को सरल बनाने तथा अनुपालन का बोझ कम करने से जुड़े सुधारों पर केंद्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ चर्चा की जाएगी। मुख्य सचिव जल जीवन मिशन, विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन 'वीबीजी राम जी', राजस्थान हाईवे मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट (आरएचएमपी), जयपुर मेट्रो तथा पीएम ई-बस सेवा से संबंधित विषयों पर केंद्रीय मंत्रालयों के साथ आगे की कार्रवाई को लेकर चर्चा करेंगे। इन बैठकों में प्रदेश की आवश्यकताओं तथा योजनाओं और परियोजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार के साथ समन्वय पर जोर रहेगा। नीति आयोग के साथ मुख्य सचिवों के छठे राष्ट्रीय सम्मेलन की तैयारियों एवं संबंधित विषयों पर भी बैठक होगी। इसके अतिरिक्त, ऊर्जा क्षेत्र के सुधारों को लेकर बैठक प्रस्तावित है।

राजस्थान में बनेगी भेड़िया संरक्षण परियोजना, हाड़ौती से होगी शुरुआत, सर्वे शुरू



प्रदेश में भेड़ियों के संरक्षण और संवर्धन के लिए वन विभाग ने व्यापक परियोजना तैयार करने की कवायद शुरू कर दी है। इसकी शुरुआत हाड़ौती के जंगलों से की गई है। रामगढ़ विषधारी और मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व सहित आस-पास के वन क्षेत्रों में भेड़ियों की मौजूदगी, संख्या और उनके विचरण क्षेत्र का पता लगाने के लिए सर्वे शुरू किया गया है। इसके लिए वन विभाग ने आमजन, वन्यजीव प्रेमियों, शोधकर्ताओं, फोटोग्राफरों और ग्रामीणों से सहयोग मांगा है। विभाग की ओर से गूगल फॉर्म भी जारी किया गया है, जिसके जरिए कोई भी व्यक्ति भेड़ियों की मौजूदगी से जुड़ी जानकारी साझा कर सकता है। वन विभाग की वन्यजीव शाखा ने कोटा संभाग के फील्ड स्टाफ के साथ शोधकर्ताओं, वन्यजीव प्रेमियों, विद्यार्थियों और संरक्षणविदों से भेड़ियों के संबंध में जानकारी उपलब्ध कराने का आग्रह किया है। सर्वे के माध्यम से उनके आवास वाले क्षेत्रों को चिह्नित कर संख्या, फैलाव और संरक्षण की संभावनाओं का आकलन किया जाएगा। इन क्षेत्रों की मैपिंग के साथ इको टूरिज्म की संभावनाएं भी तलाशी जा रही है। दोनों टाइगर रिजर्व के कोर और बफर क्षेत्रों में फोटो ट्रैप कैमरों से भी भेड़ियों की निगरानी की जा रही है। 800 हेक्टेयर वन क्षेत्र, संरक्षण के लिए चिह्नित रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व के जैव विविधता से समृद्ध भीमलत और बांका-भोपतपुरा के बफर क्षेत्र में दो वर्षों से भेड़िया संरक्षण की योजना पर काम चल रहा है। नवगठित भोपतपुरा रेंज में उपरमाल के पठार पर 800 हेक्टेयर वन क्षेत्र को भेड़ियों और गिद्धों के संरक्षण के लिए चिन्हित किया गया है। जवाहर सागर में भी दिखे भेड़ियों के झुंड मुकुंदरा टाइगर रिजर्व के अंतर्गत बूंदी जिले के जवाहर सागर अभयारण्य में भी भेड़ियों की मौजूदगी दर्ज की गई है। वन विभाग के अनुसार, यहां भेड़ियों के झुंड भी दिखाई दिए हैं। विभाग अब पूरे हाड़ौती संभाग के जंगलों में भेड़ियों के संरक्षण और उनकी संख्या बढ़ाने की संभावनाएं तलाश रहा है। व्यापक तैयारी है हाडौती क्षेत्र के जंगलों में भेड़ियों के बालस्थलों, वास्तविक संख्या, उनके प्रे-बेस (शिकार के लिए उपलब्ध वन्यजीव) के लिए आमजन व वन्यजीव प्रेमियों से व्यापक सर्वे शुरू किया है। सर्वे से प्राप्त परिणाम और वन विभाग के आंकड़ों के आधार पर भेड़ियों के संरक्षण और संवर्धन के लिए योजना तैयार की जाएगी।







280 विश्वविद्यालय, लाखों छात्र और फिर भी बदहाल उच्च शिक्षा, पाकिस्तान में क्या है संकट की वजह?

पाकिस्तान की उच्च शिक्षा व्यवस्था गंभीर वित्तीय और शैक्षणिक संकट से गुजर रही है। करीब दो दशक पहले तत्कालीन राष्ट्रपति जनरल परवेज मुशर्रफ ने देश के कॉलेजों और विश्वविद्यालयों की स्थिति बदलने के लिए बड़े सुधारों की शुरुआत की थी। इसका उद्देश्य उच्च शिक्षण संस्थानों को बेहतर बनाकर उन्हें उत्कृष्टता के केंद्र (Centres of E&cellence) के रूप में विकसित करना था। लेकिन अब इन सुधारों की सफलता पर सवाल उठ रहे हैं।पाकिस्तानी अखबार डॉन की एक रिपोर्ट के मुताबिक, पाकिस्तान में करीब 280 विश्वविद्यालय हैं और लाखों छात्र उच्च शिक्षा हासिल कर रहे हैं। देश में शोध कार्यों का दायरा भी बढ़ा है, लेकिन इसके बावजूद विश्वविद्यालय बढ़ते कर्ज, कमजोर शैक्षणिक नतीजों और शोध की गुणवत्ता को लेकर उठ रहे सवालों से जूझ रहे हैं। कई संस्थानों के लिए अपने संचालन को जारी रखना भी मुश्किल होता जा रहा है।

विश्वविद्यालयों के विस्तार से शुरू हुआ आर्थिक संकट

रिपोर्ट के अनुसार, पाकिस्तान में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सुधार के नाम पर बड़े पैमाने पर निवेश किया गया। नए विश्वविद्यालय स्थापित किए गए और अमेरिका के साथ एक महत्वपूर्ण समझौते के तहत दुनिया के सबसे बड़े फुलब्राइट स्कॉलरशिप कार्यक्रमों में से एक शुरू किया गया। इन पहलों से उम्मीद थी कि पाकिस्तान में उच्च शिक्षा और शोध को नई दिशा मिलेगी। हालांकि, दशकों बाद भी ये प्रयास अपेक्षित नतीजे नहीं दे पाए। रिपोर्ट में कहा गया है कि विश्वविद्यालयों का तेजी से हुआ विस्तार अब खुद उनके लिए आर्थिक बोझ बन गया है।

खैबर एख्तूनख्वा के विश्वविद्यालयों ने मांगा 25 अरब रुपये का पैकेज

पाकिस्तान में विश्वविद्यालयों की खराब आर्थिक स्थिति का मामला राष्ट्रीय मीडिया में भी चर्चा का विषय बना है। रिपोर्ट के मुताबिक, खैबर पख्तूनख्वा के लगभग सभी सरकारी विश्वविद्यालय गंभीर वित्तीय संकट का सामना कर रहे हैं। इन संस्थानों ने पूरे उच्च शिक्षा क्षेत्र को राहत देने के लिए करीब 25 अरब पाकिस्तानी रुपये के पैकेज की मांग की है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि विश्वविद्यालयों के सामने आर्थिक चुनौतियां कितनी गंभीर हो चुकी हैं।

2002 के सुधारों पर उठे सवाल

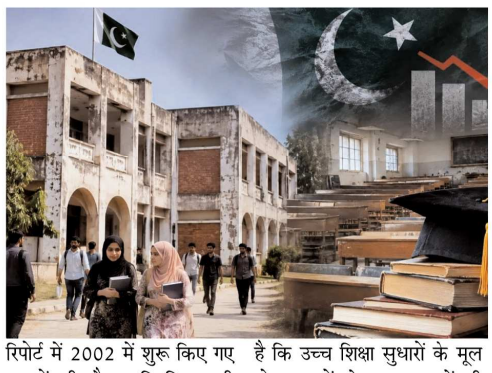

रिपोर्ट में 2002 में शुरू किए गए सुधारों की मौजूदा स्थिति पर भी सवाल उठाए गए हैं। उस समय इन सुधारों का लक्ष्य पाकिस्तान को ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था (Knowl edge Economy) में बदलना था। डॉन की रिपोर्ट में कहा गया है कि जिन सुधारों से देश के उच्च शिक्षा क्षेत्र में बदलाव की उम्मीद थी, वे अब एक ऐसी विशाल व्यवस्था में बदल गए हैं, जिसे संभालना मुश्किल हो रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक, यह व्यवस्था इतनी बड़ी हो चुकी है कि इसे विफल होने देना आसान नहीं है और इसमें सुधार करना भी कठिन होता जा रहा है।

सुधारों के शुरुआती दस्तावेज में ही जताई गई थी आशंका

रिपोर्ट का एक अहम पहलू यह भी है कि उच्च शिक्षा सुधारों के मूल योजनाकारों ने शुरुआत में ही संभावित संकट को लेकर चेतावनी दी थी। रिपोर्ट के अनुसार, 2002 की टास्क फोर्स रिपोर्ट में उच्च शिक्षा सुधारों से जुड़ी चुनौतियों और संभावित समस्याओं का जिक्र किया गया था। यही दस्तावेज आगे चलकर हायर एजुकेशन कमीशन (HEC) ऑर्डिनेंस और हायर एजुकेशन कमीशन के गठन का आधार बना। इस रिपोर्ट में पाकिस्तान के उच्च शिक्षा क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं की पड़ताल की गई है। इसमें बताया गया है कि बड़े निवेश और महत्वाकांक्षी सुधारों के बावजूद विश्वविद्यालयों की वित्तीय स्थिरता, शिक्षा की गुणवत्ता और शोध के स्तर से जुड़ी चुनौतियां बनी हुई हैं।

मुख्यमंत्री का कायमखानी समाज के साथ संवाद-शिक्षा, कौशल और आत्मनिर्भरता से सशक्त हो रहा समाज युवाओं के सपनों को साकार कर रही डबल इंजन सरका



जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि युवा सोच, वरिष्ठजनों का अनुभव और मातृशक्ति की सहभागिता विकास की नई राह प्रशस्त कर सकती है। उन्होंने बालिका शिक्षा पर जोर देते हुए कहा कि बेटियों के शिक्षित और सशक्त होने से परिवार, समाज और राष्ट्र की नींव मजबूत होती है। ऐसे में समाज के प्रबुद्धजन सामाजिक कुरीतियों को दूर करने, शिक्षा के प्रति जागरुकता बढ़ाने और जरुरतमंद परिवारों तक सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। मुख्यमंत्री रविवार को कायमखानी समाज के प्रतिनिधियों के साथ संवाद कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास' के संकल्प के अनुरूप डबल इंजन सरकार समृद्ध, सशक्त और विकसित भारत-विकसित राजस्थान के निर्माण के लिए प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है। सरकार का उद्देश्य प्रत्येक वर्ग तक शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, कौशल विकास और सामाजिक सुरक्षा सहित विभिन्न योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। शिक्षा समाज की प्रगति का आधार- न्होंने कहा कि शिक्षा और सामाजिक चेतना समाज की वास्तविक प्रगति का आधार हैं। इसी को लेकर राज्य सरकार ने छात्रावासों एवं आवासीय विद्यालयों में रहने वाले विद्यार्थियों के मैस भत्ते को 2 हजार 500 रुपये से बढ़ाकर 3 हजार 250 रुपये प्रतिमाह किया है। वहीं, विभिन्न योजनाओं के तहत 26 हजार से अधिक जरूरतमंद विद्यार्थियों को 17 करोड़ 16 लाख रुपये की छात्रवृत्ति वितरित की गई है। इसी प्रकार मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के तहत 4 हजार 786 अभ्यर्थियों को कोचिंग की सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। वहीं, प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के तहत लगभग 100 करोड़ रुपये के विकास कार्य करवाए गए हैं। गांव-गांव में अटल ज्ञान केन्द्र, युवा सपनों को दें उड़ान मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में युवाओं को पुस्तकालय, ई-लाइब्रेरी, ई-मित्र एवं ऑनलाइन सेवाओं के साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए अटल ज्ञान केन्द्र स्थापित किए जा रहे हैं। जिनके माध्यम से युवाओं को पढ़ने के लिए संबंधित आवश्यक सुविधाएं गांव में ही उपलब्ध हो रही हैं, जिससे उनका शहरों की ओर पलायन रूकेगा। मुख्यमंत्री ने युवाओं से अपील करते हुए कहा कि राज्य सरकार निरंतर भर्ती परीक्षाएं पूर्ण पारदर्शिता से आयोजित करवा रही है। युवा मन लगाकर पढ़ें, डबल इंजन सरकार उनके सपनों को साकार करने के लिए साथ खड़ी है। ऐतिहासिक जल समझौते उत्तर रहे धरातल पर- उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में राज्य सरकार ने प्रदेश में जल उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए ऐतिहासिक पहल की है। पानी से जुड़े 2 लाख करोड़ रुपये से अधिक के कार्य हाथ में लिए गए हैं। दशकों से लंबित रामजल सेतु लिंक परियोजना, यमुना जल और किशाऊ समझौते सहित विभिन्न परियोजनाओं को धरातल पर उतारने का कार्य किया जा रहा है। इससे पेयजल, सिंचाई और औद्योगिक विकास के लिए पानी मिलेगा और अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी।



सतत विकास लक्ष्य की तरह ही हर विद्यालय तय करे विद्यालय विकास

लक्ष्य- सचिव, केन्द्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता

जयपुर। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के विकसित भारत-2047 के लक्ष्य को पूर्ण करने में आज के स्कूली विद्यार्थियों की महत्वपूर्ण भूमिका है। 20 साल बाद यही युवा इसकी नींव होंगे। आज के स्कूली बच्चों को कुशल, दक्ष, जिम्मेदार नागरिक और पर्यावरण के प्रति जागरूक बनाना अति आवश्यक है। यह विचार केन्द्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के सचिव सुधांश पंत ने विद्या भवन सोसायटी द्वारा आयोजित सीड-2 कॉन्फ्रेंस के उद्घाटन समारोह में व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि स्कूल में पढ़ रहे बच्चों को बदलते विश्व के अनुरूप ज्ञान, मूल्यों और प्रायोगिक कौशल को उपलब्ध कराना जरूरी है। यह स्कूलों के माध्यम से ही संभव है।उन्होंने मिशन लाइफ पर फोकस करते हुए विद्यार्थियों को पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली की ओर प्रवृत्त करने का आह्वान किया और इसके लिए अध्यापकों के योगदान को महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि नशा मुक्त भारत के लिए और वरिष्ठ नागरिकों के सम्मान के लिए अध्यापकों को बच्चों को अभी से सीख देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत सरकार के मिशन लाइफ, कैच द रैन, नशा मुक्ति अभियान, एक पेड़ माँ के नाम जैसी योजनाओ का हर विद्यालय प्रभावी क्रियान्वयन करे। बेहतर भविष्य के निर्माण के लिए हमें आज से ही सकारात्मक प्रयास करने होंगे। विद्यार्थी जीवन में अनुशासन एवं संस्कार आदतें जीवनभर साथ रहते हैं। उन्होंने कहा कि सतत विकास लक्ष्य की तरह हो विद्यालय विकास लक्ष्य निर्धारित हो जिसमें प्रतिवर्ष ऊर्जा खपत मे कमी, जल खपत मे कमी, जल बचत, कचरा उत्सर्जन मे कमी का आंकलन हो । उन्होंने कहा कि शिक्षा केवल किताबी ज्ञान अर्जित करने या परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने तक सीमित नहीं रहे तरह बदलते हुए जगत में विद्यार्थियों को स्कूल द्वारा किस तरह से तैयार किया जाये, जैसे महत्वपूर्ण विषयो को लेकर विद्या भवन द्वारा तीन दिवसीय शैक्षिक सम्मेलन 'सीड-2' फॉर सस्टेनिंग फ्यूचर्स का आयोजन किया जा रहा है। सम्मेलन की रूपरेखा हर्थ एडवाइजर्स द्वारा तैयार की गई है। प्रायोजक जे एस डब्लू एनर्जी तथा वीवा फाउंडेशन है। इस आयोजन में शिक्षाविद्, विद्यालय प्रमुख, नीति निर्माता और विभिन्न संस्थानों के प्रतिनिधि एक मंच पर एकत्रित होकर विचार-विमर्श कर रहे है कि तेजी से बदलती दुनिया में बच्चों को बेहतर भविष्य के लिए कैसे तैयार किया जाए। पूर्व केन्द्रीय शिक्षा सचिव तथा नई राष्ट्री शिक्षा निति के निर्माण में प्रमुख भूमिका निभाने वाले संजय कुमार ने मुख्य वक्ता के रूप में कहा कि जब कोई हमको देख नहीं रहा हो, तब भी हम अपना कार्य पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करें, ऐसी शिक्षा विद्यालयो मे मिलनी चाहिये। उन्होंने अपने विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने तथा आत्मविश्वास के साथ बोलने की कला विकसित करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि विद्यालयों में केवल परीक्षा आधारित मूल्यांकन ही नहीं, बल्कि विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास का आकलन भी आवश्यक है। इसके लिए चार महत्वपूर्ण पहलुओं पर विशेष ध्यान देना चाहिए-बच्चे क्या सीख रहे हैं, उन्होंने नया क्या सृजन किया है, उनके द्वारा कौन-सी नई तकनीक विकसित की गई है तथा नवाचार एवं तकनीकी विकास के लिए उन्हें किस प्रकार के संसाधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। उन्होंने कहा स्कूली जीवन मे मिले शिक्षा, संस्कार, अनुशासन, एवं नवाचार जीवन भर साथ चलते है।





पंचायतीराज आम चुनाव के तृतीय चरण के लिए मतदान दल आज अंतिम प्रशिक्षण के बाद होंगे रवाना

जयपुर। जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) संदेश नायक ने रविवार को श्री भवानी निकेतन कॉलेज ऑफ फार्मेसी, सीकर रोड परिसर का दौरा कर तृतीय चरण के मतदान दलों की रवानगी एवं निर्वाचन संबंधी व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने मतदान दलों के अंतिम प्रशिक्षण, निर्वाचन सामग्री वितरण, वाहन पार्किंग तथा मतदान दलों की सुविधा के लिए की गई व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों को सभी व्यवस्थाएं समयबद्ध एवं सुव्यवस्थित ढंग से सुनिश्चित करने तथा मतदान दलों को किसी प्रकार की असुविधा नहीं होने देने के निर्देश दिए। जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) संदेश नायक ने बताया कि पंचायतीराज आम चुनाव के तहत जयपुर जिले में तृतीय चरण के मतदान की तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। इसके लिए 2 नवंबर को मतदान दल अंतिम प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद श्री भवानी निकेतन कॉलेज ऑफ फार्मेसी परिसर से संबंधित मतदान केंद्रों के लिए रवाना होंगे। उन्होंने बताया कि मतदान दलों को अंतिम प्रशिक्षण के दौरान मतदान प्रक्रिया, ईवीएम के संचालन, बैलेट पेपर तथा निर्वाचन संबंधी आवश्यक दिशा-निर्देशों की जानकारी दी जाएगी। प्रशिक्षण के पश्चात मतदान दलों को निर्वाचन सामग्री एवं अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं के साथ संबंधित मतदान केंद्रों के लिए रवाना किया जाएगा। मतदान दलों की सुविधा के लिए वाहन पार्किंग एवं अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं भी सुनिश्चित की गई हैं। उन्होंने बताया कि तृतीय चरण के तहत जिला परिषद के वार्ड संख्या 27 से 37, जयपुर जिले की पांच पंचायत समितियों चाकसू, कोटखावदा, माधोराजपुरा, फागी एवं सांगानेर में जिला परिषद् एवं पंचायत समिति सदस्य तथा पंच-सरपंच पदों के लिए मतदान कराया जाएगा। इस चरण में चाकसू पंचायत समिति के 17 पंचायत समिति वार्ड और 32 ग्राम पंचायतों के लिए 93 मतदान केंद्र, कोटखावदा के 15 पंचायत समिति वाड और 27 ग्राम पंचायतों के लिए 82 मतदान केंद्र, माधोराजपुरा के 15 पंचायत समिति वार्ड और 25 ग्राम पंचायतों के लिए 93 मतदान केंद्र, फागी के 15 पंचायत समिति वार्ड और 26 ग्राम पंचायतों के लिए 90 मतदान केंद्र तथा सांगानेर के 15 पंचायत समिति वार्ड और 23 ग्राम पंचायतों के लिए 84 मतदान केंद्र निर्धारित किए गए हैं। इन क्षेत्रों में कुल 3 लाख 74 हजार 816 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, जिनमें 1 लाख 93 हजार 206 पुरुष, 1 लाख 81 हजार 609 महिला तथा एक अन्य मतदाता शामिल हैं।


शोक संदेश

अत्यंत दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि हमारी पूजनीय

तुलछी देवी

(पत्नी स्व. किशनाराम सहू, पीटीआई)

निवासी कुंतासर का स्वर्गवास दिनांक 18 अक्टूबर 2026 वार रविवार को हो गया है। जिनका बाहरवां 29 अक्टूबर 2026 वार गुरुवार को है।

शोकाकुल : मनीराम-ज्यानी देवी जाखड़ (दामाद-बेटी), नितेश, गीता, रणजीत, निशा (दोहिता-दोहिती), सुगनाराम सहु (जेठ) सुखाराम सहू (देवर), हड़मानाराम, बीरबलराम, रामकरण, मूलाराम, सीताराम (जेठ पुत्र), श्रवण, विनोद (देवर पुत्र), सुरेन्द्र, रामनिवास, मनोज, गोविन्द, सहीराम, पवन, पंकज, भावेश, मुकेश, कार्तिक (पौत्र)।

गांव कुंतासर, श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर) मो.96728 03776

संजू सैमसन या अभिषेक शर्मा नहीं, हैमिल्टन टी20 में इन 2 खिलाड़ियों की वजह से टीम इंडिया को मिली हार!



हैमिल्टन में खेले गए पांच मैचों की टी20 सीरीज के आखिरी मुकाबले में भारतीय टीम को 7 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। न्यूजीलैंड ने 192 रन के लक्ष्य को 18 ओवर में ही सिर्फ 3 विकेट गंवाकर हासिल कर लिया। इस दौरान टीम इंडिया के गेंदबाज विकेट के लिए तरसते रहे और रन भी नहीं रोक पाए। अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती और नीतीश कुमार रेड्डी को एक-एक सफलता जरूर मिली, लेकिन ये विकेट टीम इंडिया को जीत दिलाने के लिए काफी नहीं थे।

एडम मिल्ने ने 4 ओवर में दिए 19 रन

इस मुकाबले में टीम इंडिया की हार की सबसे बड़ी वजह दो गेंदबाज रहे। भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 191 रन बनाए। लेकिन न्यूजीलैंड के गेंदबाजों ने शुरुआत से ही भारतीय बल्लेबाजों पर दबाव बनाए रखा। संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा को एडम मिल्ने ने एक के बाद एक आउट कर दिया। शुरुआती पिच से मिल रही मदद का न्यूजीलैंड के गेंदबाजों ने पूरा फायदा उठाया। एडम मिल्ने ने 4 ओवर में सिर्फ 19 रन देकर 4 विकेट चटकाए। वहीं, जैकब डफी, नाथन स्मिथ और ब्लेयर टिकनर ने भी शानदार गेंदबाजी की। कप्तान मिचेल सेंटनर का इकोनॉमी रेट भी 10 से कम रहा। दूसरी ओर, टीम इंडिया के दो अनुभवी गेंदबाज इस मुकाबले में पूरी तरह असफल साबित हुए। भुवनेश्वर कुमार ने 4 ओवर में 41 रन दिए और एक भी विकेट हासिल नहीं कर पाए। वहीं, अर्शदीप सिंह ने 4 ओवर में 40 रन खर्च किए। हालांकि, उन्हें एक विकेट जरूर मिला, लेकिन वह भी रन रोकने में नाकाम रहे। न्यूजीलैंड की ओर से टिम साइफर्ट ने 50 गेंदों में 93 रन ठोक डाले, जिसमें 5 छक्के और 11 चौके शामिल थे। वहीं, डैरिल मिचेल ने सिर्फ 16 गेंदों में 4 छक्कों की मदद से 29 रन बना डाले। इसके अलावा इस सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले ग्लेन फिलिप्स भारतीय गेंदबाजों पर कहर बनकर टूटे। उन्होंने 38 गेंदों में 65 रन की पारी खेली, जिसमें 8 चौके और 3 छक्के शामिल थे।

नहीं काम आया भुवी का अनुभव

टीम इंडिया के गेंदबाज इन तीनों बल्लेबाजों को रोकने में नाकाम रहे और न्यूजीलैंड ने 2 ओवर पहले ही मुकाबला खत्म कर दिया। इस हार की सबसे बड़ी वजह भुवनेश्वर कुमार और अर्शदीप सिंह की महंगी गेंदबाजी रही। दोनों टीम इंडिया के अनुभवी गेंदबाज हैं, लेकिन इस मुकाबले में न तो उनका अनुभव नजर आया और न ही विकेट हासिल करने की कोई प्लान। जिसकी वजह से न्यूजीलैंड ने 192 रन का लक्ष्य आसानी से हासिल कर लिया।

पूर्व अनुमोदित योजनाओं में एचटी लाइन हटने पर प्रभावित भूखंडों का अनुमोदन एवं पट्टा जारी करने की कार्यवाही जोन स्तर पर

जयपुर। जयपुर विकास प्राधिकरण (जेडीए) ने आमजन की सुविधा एवं लंबित प्रकरणों के त्वरित निस्तारण की दिशा में महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय लेते हुए उन भूखंडों के अनुमोदन एवं पट्टा जारी करने की प्रक्रिया को सरल बना दिया है, जिन पर पूर्व में हाईटेंशन (एचटी) विद्युत लाइन होने के कारण पट्टा जारी नहीं हो पा रहा था, लेकिन वर्तमान में मौके से एचटी लाइन हटाई जा चुकी है। जेडीए की दिनांक 18 अगस्त, 2026 को आयोजित भवन मानचित्र समिति की 437वीं बैठक में इस संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। इसके तहत ऐसे प्रकरणों में, जहां मौके से एचटी लाइन हटाई जा चुकी है, संबंधित भूखंडों के अनुमोदन एवं पट्टा जारी करने की कार्यवाही अब जोन स्तर पर ही संपादित की जा सकेगी। इस निर्णय की प्रभावी क्रियान्विति सुनिश्चित करने के क्रम में जेडीए द्वारा 31 अक्टूबर, 2026 को नवीन आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। जेडीए द्वारा जारी आदेश अनुसार पूर्व में अनुमोदित योजनाऐं जिनमें अनुमोदन के समय एचटी लाईन स्थित होने से, एचटी लाइन कॉरिडोर से प्रभावित भूखण्डों को गैर अनुमोदित रखा गया था अथवा एचटी लाईन कॉरीडोर को छोडते हुए शेष भाग का अनुमोदन किया गया था। ऐसे प्रकरणों में (जिनमें एचटी लाईन के सहारे सड़क प्रस्तावित नही है) वर्तमान में एचटी लाईन शिफ्ट किये जाने / हटाये जाने की स्थिति में जोन स्तर पर एचटी लाईन से प्रभावित भाग को सम्मिलित करने पर योजना के विक्रय योग्य क्षेत्रफल नियमानुसार मापदण्डों के अनुरूप होने पर गुणावगुण आधार पर मूल मानचित्र में संशोधन जोन स्तर पर ही किया जाकर, प्रभावित भूखण्डों की लीजडीड / संशोधित लीजडीड जारी की जा सकेगी। इस आदेश के साथ ही ऐसे प्रकरणों में अनुमोदन की कार्यवाही भी जेडीए द्वारा प्रारंभ कर दी गई है। उल्लेखनीय है कि आमजन द्वारा समय-समय पर जेडीए के समक्ष यह समस्या उठाई जा रही थी कि पूर्व में भूखंडों के ऊपर से एचटी लाइन गुजरने के कारण उनके पट्टे जारी नहीं हो पाए थे, जबकि वर्तमान में मौके से एचटी लाइन हटाई जा चुकी है। इसके बावजूद पूर्व की प्रक्रिया के चलते उनके प्रकरण लंबित थे। आमजन की इस व्यावहारिक समस्या को गंभीरता से लेते हुए जेडीए द्वारा यह जनहितकारी नीतिगत निर्णय लिया गया है। इससे एचटी लाइन हटाए जाने के बाद भी पट्टे के लिए लंबित भूखंडों के प्रकरणों का त्वरित निस्तारण संभव होगा। साथ ही, जोन स्तर पर ही अनुमोदन एवं पट्टा जारी करने की कार्यवाही होने से प्रक्रियात्मक जटिलताओं में कमी आएगी तथा आमजन को कार्यालय ?के अनावश्यक चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।



